त्यौहारी सीजन में टॉप गियर पर वाहन बिक्री

42 दिनों में कंपनियों ने रिकॉर्ड 55.3 लाख वाहन बेचे

10 वाहनों में एक ईवी की बिक्री

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 नवंबर. देश में इस साल त्यौहारी सीजन के दौरान वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है. नवरात्रि से लेकर धनतेरस के बाद तक चले 42 दिनों के त्योहारी सीजन में कुल 55.3 लाख वाहन बिके, जो पिछले साल के मुकाबले 2.2 फीसदी ज्यादा हैं.

हालांकि, इस बार सबसे ज्यादा चर्चा इलेक्ट्रिक वाहनों की रही. पहली बार किसी एक त्योहारी सीजन में पांच लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिके. दिलचस्प बात यह है कि जहां



इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ी, वहीं सामान्य पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी की कुल बिक्री में गिरावट देखने को मिली. यह जानकारी वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस फाडा ने दी है. फाडा के मुताबिक, त्यौहारी सीजन में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 52.62 फीसदी बढ़कर पांच लाख यूनिट के पार पहुंच गई. यानी इस दौरान बिकने वाले हर 10 वाहनों में करीब एक इलेक्ट्रिक था. इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 61.10 फीसदी और इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में 72.91 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. वहीं, इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की बिक्री दोगुने से ज्यादा हो गई. पिछले दो साल की तुलना करें तो त्यौहारी सीजन में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 68 फीसदी बढ़ चुकी है. त्यौहारी सीजन में पैसेंजर व्हीकल कैटेगरी की कुल बिक्री 7.16 फीसदी घट गई.

हालांकि, बाकी सभी कैटेगरी में बढ़ोतरी दर्ज की गई. दोपहिया वाहनों की बिक्री 3.67 फीसदी, कमर्शियल वाहनों की 7.13 फीसदी, तिपहिया वाहनों की 5.32 फीसदी और ट्रैक्टर की बिक्री 2.24 फीसदी बढ़ी.

कम सप्लाई से बिक्री प्रभावित

फाडा के अध्यक्ष साई गिरिधर के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग काफी मजबूत रही, लेकिन पर्याप्त स्टॉक नहीं होने से बिक्री और ज्यादा नहीं बढ़ सकी. डीलरों को इलेक्ट्रिक दोपहिया और पैसेंजर व्हीकल, दोनों कैटेगरी में वाहनों की कमी का सामना करना पड़ा. उनका कहना है कि अगर कंपनियों के पास पर्याप्त वाहन होते, तो त्यौहारी सीजन में 60,000 से 70,000 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहन बिक सकते थे. सप्लाई की कमी के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की कुल बाजार हिस्सेदारी संभावित 11 फीसदी से ज्यादा के स्तर के बजाय करीब 9 फीसदी रही.

सालभर की बिक्री का रिकॉर्ड भी संभव

फाडा के मुताबिक, देश में कैलेंडर वर्ष 2026 के दौरान पहली बार कुल वाहन बिक्री तीन करोड़ यूनिट का आंकड़ा पार कर सकती है. संगठन ने पूरे साल में 3.1 से 3.2 करोड़ वाहन बिकने का अनुमान जताया है. इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल की सालाना बिक्री भी पहली बार 50 लाख यूनिट के पार पहुंच सकती है. गिरिधर के मुताबिक, जीएसटी 2.0 के बाद वाहनों की कीमतों में आई राहत, घरेलू मांग और इलेक्ट्रिक समेत अलग-अलग विकल्पों की उपलब्धता से ऑटो सेक्टर को फायदा मिल रहा है.

यूपीआई से पीएफ निकासी होगी आसान

▶ पैसा निकालने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंची

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 नवंबर. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों सदस्यों के लिए अच्छी खबर है. अब जल्द ही पीएफ का पैसा निकालने के लिए लंबी ऑनलाइन प्रक्रिया और क्लेम सेटलमेंट का इंतजार नहीं करना पड़ेगा.

ईपीएफओ दिसंबर 2026 के अंत तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई के जरिए पीएफ निकासी की सुविधा शुरू कर सकता है. इस सुविधा के तहत कर्मचारी भीम ऐप की मदद से अपना पात्र पीएफ बैलेंस सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, यूपीआई से पीएफ निकासी की सुविधा का तकनीकी परीक्षण पूरा



हो चुका है. ट्रायल के दौरान सामने आई खामियों को भी दूर कर लिया गया है. फिलहाल यह सुविधा शुरू करने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. हालांकि, ईपीएफओ ने लॉन्च की तारीख को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की है. नई व्यवस्था लागू होने के बाद कर्मचारियों को पीएफ खाते की जानकारी के लिए बार-बार ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगइन नहीं करना होगा. भीम ऐप के जरिए सदस्य तीन अहम जानकारियां देख सकेंगे. इनमें खाते में कुल उपलब्ध निकासी योग्य राशि, वास्तव में निकाली जा सकने वाली रकम और रिटायरमेंट खाते में सुरक्षित रखी जाने वाली न्यूनतम राशि शामिल है.

निकासी के नियमों में भी हुए बदलाव

ईपीएफओ ने आंशिक निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 13 अलग-अलग प्रावधानों को तीन प्रमुख श्रेणियों में व्यवस्थित किया है. इनमें जरूरी जरूरतें, आवास संबंधी जरूरतें और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं. शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार तक आंशिक निकासी की अनुमति का प्रावधान भी किया गया है. इसके अलावा पात्र एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-सेटलमेंट की सीमा 5 लाख रुपए है. इससे कर्मचारियों को जरूरत के समय जल्दी पैसा मिल सकेगा.

वैश्विक चीनी उत्पादन में गिरावट का अनुमान

▶ चीनी कीमतों में उबाल की आशंका

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 नवंबर. चीनी उद्योग के लिए 2026-27 का पेराई सीजन (अक्टूबर-सितंबर) चुनौतियों और अस्थिरता से भरा साबित हो रहा है.

मौसम की अनियमितता और प्रमुख उत्पादक देशों में फसल को हुए नुकसान के कारण वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर चीनी उत्पादन में गिरावट दर्ज की जा रही है. वैश्विक चीनी उत्पादन में लगभग 5 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान है. उत्पादन घटकर 17.81 करोड़ मीट्रिक टन रह सकता है. आपूर्ति में इस



संभावित कमी से अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय थोक और खुदरा मंडियों तक चीनी की कीमतों को नई ऊंचाई पर पहुंचा सकता है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी की आपूर्ति श्रृंखला दबाव में है. अमेरिकी कृषि विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2026-27 सीजन में वैश्विक चीनी उत्पादन करीब 5 प्रतिशत घटकर 17.81 करोड़ टन रहने का अनुमान है, जो पिछले सीजन में 18.71 करोड़ टन था.

फ्लेक्सीकैप फंड्स में 6 महीने में घटा निवेश

नई दिल्ली, 23 नवंबर. फ्लेक्सीकैप म्यूचुअल फंड्स में पिछले एक साल के दौरान निवेशकों ने जमकर पैसा लगाया है. लेकिन हाल के महीनों में निवेश की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है. नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच इन फंड्स में हर महीने औसतन करीब 8,826 करोड़ रुपये का निवेश आ रहा था, जो मई से अक्टूबर 2026 के दौरान घटकर 5,310 करोड़ रुपये रह गया. यानी पहले के छह महीनों के मुकाबले पिछले छह महीनों में औसत मासिक निवेश करीब 40 फीसदी घट गया. अक्टूबर में भी इस कैटेगरी में करीब 4,980 करोड़ रुपये का निवेश आया है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि निवेश की रफ्तार घटने का मतलब निवेशकों का भरोसा कम होना नहीं है.

सिर्फ कमाई बढ़ना काफी नहीं : वित्त मंत्री

दोबारा गरीबी में फंसने से रोकेगा डिजिटल इकोसिस्टम और सस्ता कर्ज

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 नवंबर. देश से गरीबी के स्थायी खात्मे और कमजोर तबकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने अपना नीतिगत एजेंडा स्पष्ट किया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेखांकित किया कि भारत में गरीबी उन्मूलन को स्थायी बनाने और गरीबी से बाहर निकले परिवारों को दोबारा उस दलदल में फिसलने से रोकने के लिए वित्त (फाइनेंस), बाजार और डिजिटल अर्थव्यवस्था (डिजिटल इकोसिस्टम) तक व्यापक पहुंच सबसे अहम होगी. उन्होंने विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2011 से 2023 के बीच लगभग 50 करोड़



सीतारमण ने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अभावों को दूर करने के लिए लक्षित हस्तक्षेपों, मापने योग्य परिणामों और कस्टमाइज्ड योजनाओं पर काम किया है. जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना और स्वच्छ भारत जैसी प्रमुख योजनाएं संयुक्त रूप से उन अप्रत्याशित वित्तीय झटकों के खिलाफ 'बीमा' का काम कर रही हैं, जो पहले परिवारों को गरीबी में धकेल दिया करते थे. इन योजनाओं ने न केवल घरेलू खर्चों को काफी कम किया है, बल्कि आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं का समय भी बचाया है जिससे वे रोजगार व काम में अधिक समय दे पा रही हैं. वित्त मंत्री के अनुसार, कल्याणकारी योजनाओं की सुरक्षा परिवारों को दोबारा गरीब बनने से रोकती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्हें कमाने के ठोस अवसरों की जरूरत है.

भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, और अब सरकार का पूरा ध्यान ऐसे संस्थागत सुरक्षा घेरे तैयार करने पर है जिससे उनकी आर्थिक तरक्की निर्बाध जारी रहे. वित्त मंत्री ने गरीबी के पारंपरिक नजरिए पर सवाल उठाया. उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीबी केवल आय या वेतन की कमी भर नहीं है. जिस परिवार के पास पक्की छत, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता या बुनियादी स्वास्थ्य सेवा नहीं है, वह कमाई बढ़ने के बावजूद बेहद संवेदनशील बना रहता है.

आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों ने बैंक के वैल्यूएशन पर उठाए सवाल

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 नवंबर. सार्वजनिक क्षेत्र के आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने निजीकरण से पहले सरकार द्वारा किये गये बैंक के वैल्यूएशन पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए और निजीकरण को रद्द करने की मांग की है.

आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के यूनाइटेड फोरम ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि किस आधार पर उन्होंने बैंक की 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा के फेयरफैक्स समूह को 81 रुपये प्रति शेयर के भाव पर (52,878.08 करोड़ रुपये में) बेचने की मंजूरी दी. पहले दौर की बोली के समय 94.42 रुपये प्रति शेयर के आरक्षित मूल्य को बाद में बदलकर 75.99 रुपये किए जाने पर फोरम ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. सरकार ने कहा था कि बाद में किए गए दो मूल्यांकनों का औसत 75.99 रुपये प्रति शेयर था और इसी के आधार पर सफल बोली का आकलन किया गया. फोरम ने इस बदलाव की पूरी तरह से सार्वजनिक जांच की मांग की है. उसने कहा कि बाद में अपनाई गई मूल्यांकन प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के आंकड़ों को तुलना के लिए आधार माना गया था, जो गलत है.

सोना 16 दिन गिरने के बाद 1230 रु. महंगा

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 नवंबर. सोना के दाम लगातार 16 दिन गिरने के बाद आज यानी 23 नवंबर को बढ़ गए हैं. 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,230 रुपए महंगा होकर 1.25 लाख रुपए पर पहुंच गया है. पांच नवंबर को सोने के दाम 1.44 लाख रुपए पर थे, जो लगातार गिरावट के बाद 1.24 लाख रुपए पर आ गए थे.

एक किलो चांदी की कीमत सोमवार 413 रुपए बढ़कर 1.53 लाख रुपए हो गई है. एक्सपर्ट्स के अनुसार लगातर गिरावट के कारण अब सोने-चांदी में खरीदारी बढ़ने



▶ 10 ग्राम सोना का दाम 1.25 लाख रुपए पहुंचा

लगी है, लेकिन अभी एकमुश्त खरीदारी से बचना चाहिए. वहीं एमसीएक्स पर सोने की कीमत कारोबार के दौरान 3700 रुपये से अधिक उछली जबकि चांदी की कीमत में 6100 रुपये से ज्यादा तेजी आई. अमेरिका में फेड रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना के बावजूद सोने और चांदी की कीमत में तेजी आई है. एमसीएक्स पर चार दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 121778 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था. आज यह 124443 रुपये पर खुला. कारोबार के दौरान यह 3738 रुपये की तेजी के साथ 125516 रुपये तक उछला. दोपहर बाद 2.30 बजे यह 2854 रुपये यानी 2.34 फीसदी तेजी के साथ 124632 रुपये पर ट्रेड कर रहा था.

एसएंडपी का अनुमान : अल नीनों के चलते बढ़ेगी महंगाई

▶ चालू वित्तीय वर्ष में सात फीसदी रहेगी भारत की वृद्धि दर

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 नवंबर. भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2027 में सात फीसदी की दर से बढ़ सकती है. साथ ही, अल नीनो के असर से खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा दिख सकता है.

वैश्विक रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने सोमवार को यह अनुमान जताया है. एजेंसी ने आने



वाले वित्तीय वर्ष के लिए सात फीसदी की वृद्धि दर का अनुमान जताते हुए कहा है कि भारत 2027 में भी एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बना रहेगा. ग्लोबल रेटिंग्स ने अनुमान लगाया है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि चालू और अगले वित्त वर्ष में 7 फीसदी रहेगी.

स्पाइसजेट की वित्तीय जांच की मांग

▶ पायलट संघ ने केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू को लिखी चिट्ठी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 नवंबर. फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए से एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट की वित्तीय स्थिति और सुरक्षा व्यवस्था का तत्काल आकलन करने की मांग की.

संघ ने ये भी कहा कि एयरलाइन की वित्तीय मुश्किलों का कर्मचारियों, खासतौर पर क्रू मेंबर्स के कल्याण



और कामकाज पर पड़ने वाले असर की जांच की जानी चाहिए.

फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने नागर विमानन मंत्री के. राममोहन नायडू को लिखी चिट्ठी में स्पाइसजेट के मामले में मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है. उसने सभी शेड्यूल्ड एयरलाइन कंपनियों की वित्तीय स्थिति की सालाना व्यापक समीक्षा करने का भी सुझाव

एयरलाइन की सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का आकलन करने की मांग

स्पाइसजेट के मामले में पायलट संघ ने एयरलाइन की सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, क्रू मेंबर्स की थकान से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन और कर्मचारियों के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं की जानकारी देने के माहौल का आकलन करने की मांग की है. चिट्ठी में ये भी कहा गया है कि नौकरी की असुरक्षा या आर्थिक तंगी से जूझ रहे कर्मचारी थकान, परिचालन संबंधी समस्याओं या सुरक्षा में खामियों की जानकारी देने से बच सकते हैं.

समाचार विशेष

'मथुरा में कमल खिला दे आगरा में दमदार दलित'

▶ ब्रज में बिछने लगी 2027 की सियासी बिसात

मथुरा, 23 नवंबर. दलितों के गढ़ आगरा में 15 नवंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव दलित महासम्मेलन में पीडीए के डी को दमदार दलित बताकर सामाजिक समीकरण साध रहे थे. वहीं, 16 और 17 नवंबर को यहां से 42 किलोमीटर दूर धर्मक्षेत्र मथुरा के परखम में भाजपा राधे-राधे, कमल खिला दे, अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी और भाजपा 2027 में अंगद पांव जैसे नारों के साथ सुरक्षा, सुशासन और विकास का एजेंडा लेकर चुनाव में उतरने की रणनीति बना रही थी.

चुनावी बादलों की उमड़-घुमड़ के बीच 65 विधानसभा सीटों वाला ब्रज क्षेत्र राजनीति की नई प्रयोगशाला बन रहा है. यहां की रज में धर्म की तरंग, जातीय समीकरणों में बेचैनी भी है. विकास, रोजगार और प्रत्याशियों को बदलने का विमर्श तैर रहा है तो ब्रज क्षेत्र में वादे अधूरे रहने का दर्द भी है. यहां पार्टी से ज्यादा प्रत्याशियों को बदलने की व्यग्रता दिखाई देती है.

भाजपा और सपा के रथ आमने-सामने खड़े हो रहे हैं. भाजपा उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में जुटी है. वहीं सपा यादव, मुस्लिम और तीसरी जाति को जोड़कर जीत का पहाड़ चढ़ने की तैयारी में है. बसपा नए तेवर के साथ जमीन मजबूत करने में जुटी है. प्रतीक्षालय में खड़े सहयोगी दलों का स्थान तय होना बाकी है. जनता जातीय समीकरणों पर भरोसा करे या सुशासन के दावों पर मुहर लगाए, यह सवाल नया विमर्श खड़ा कर रहा है. वर्ष 2014 से ब्रज क्षेत्र भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है. वर्ष 2017 में यहां 65 विधानसभा सीटों में से 57 पर भाजपा ने जीत दर्ज की, जबकि वर्ष 2022 में 53 सीटों पर कमल खिला.



भाजपा के जातीय समीकरण प्रभावित करने की रणनीति

पिछले लोकसभा चुनाव में सपा ने भाजपा से बदायूं, आंवला, फिरोजाबाद और एटा सीटें छीन ली थीं. जहां भाजपा जीती, वहां भी पिछले चुनाव की तुलना में 60 हजार तक वोट कम हो गए. इससे सपा का मनोबल बढ़ा है. ब्रज में भाजपा के रथ को रोकने के लिए सपा की आगरा से मैनपुरी तक कई सीटों पर भाजपा के जातीय समीकरण को प्रभावित करने की रणनीति दिखती है.

मोदी के नेतृत्व में 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर : शिवराज

गरीबी उन्मूलन में कृषि व ग्रामीण विकास की भूमिका पर आयोजित कार्यशाला की केंद्रीय मंत्री चौहान ने की अध्यक्षता



नवभारत न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली, 23 नवंबर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अभूतपूर्व, अकल्पनीय और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है. वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, देश में करीब 50 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं और अत्यंत गरीबी की दर 27.1 प्रतिशत से घटकर मात्र 2.6 प्रतिशत रह गई है.

इस असाधारण उपलब्धि में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, कृषि अनुसंधान, भूमि संसाधन तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के योगदान पर मंथन करने और आगे की रणनीति तय करने के लिए आज नई दिल्ली स्थित अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस संयुक्त कार्यशाला में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने भी सहभागिता की. शिवराज सिंह ने इस सफलता को असाधारण, अकल्पनीय और अभूतपूर्व चमत्कार बताया. कार्यशाला में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो उपलब्धि हासिल की है, वह सचमुच असाधारण, अद्भुत और अकल्पनीय है. स्वयं वर्ल्ड बैंक ने माना है कि दुनिया के किसी भी देश में इतनी तेजी से गरीबी कम नहीं हुई है. चौहान ने कहा कि कहने को 50 करोड़ का आंकड़ा आसान लगता है, लेकिन यदि हम तुलना करें तो अमेरिका की कुल आबादी लगभग 30 करोड़ है और पूरे यूरोप की आबादी भी मिला दें तो शायद 50 करोड़ न हो. इतने विशाल जनसमूह का गरीबी की रेखा से ऊपर उठना एक ऐतिहासिक घटना है. इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व, उनका विजन और उनका परिश्रम तो है ही, साथ ही दोनों मंत्रालयों के हर अधिकारी और कर्मचारी की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है.

राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ की धमक

रायपुर, 23 नवंबर. भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन में छत्तीसगढ़ को फिर अहम प्रतिनिधित्व मिला है. पार्टी ने राज्य के दो प्रमुख नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. दुर्ग ग्रामीण से भाजपा विधायक ललित चंद्राकर को पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है.

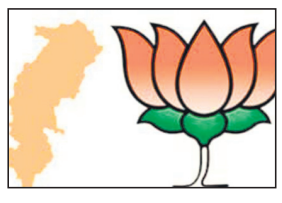

पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से जारी सूची में छत्तीसगढ़ के खम्हन ताम्रकार को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है. उन्हें ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति का सदस्य नियुक्त किया गया है. देश के अलग-अलग राज्यों के नेताओं को भी इस नई कार्यकारिणी में शामिल किया गया है. भाजपा के इस फैसले को छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों के अनुसार इससे ओबीसी वर्ग के बीच पार्टी की पकड़ और मजबूत होगी. ललित चंद्राकर को राष्ट्रीय महामंत्री पद मिलना प्रदेश संगठन के लिए बड़ी उपलब्धि है. वहीं खम्हन ताम्रकार के जुड़ने से राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व बढ़ा है.

जारी आधिकारिक आदेश के मुताबिक यह नियुक्तियां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर हुई हैं. आदेश में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है. पार्टी ने इन सभी नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है.

उत्तर मध्य रेलवे

सं.: AGC-EL-C-BIB-SOE-Public Notification | दिनांक : 23.11.2026

भारतीय रेल

''सार्वजनिक अधिसूचना''

रेलवे लाइनों, परिसरों और सभी समपार फाटकों के सभी उपयोगकर्ताओं को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी मण्डल के निम्नलिखित खण्डों पर 25000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, ए.सी. शिरोपरि कर्षण तार को खण्ड में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके बाद ऊर्जित किया जायेगा उस तारीख और उस तारीख के बाद से शिरोपरि कर्षण लाइन को हर समय विद्युतमय माना जायेगा और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति शिरोपरि लाइन के सामीप्य में दाखिल नहीं होगा या काम नहीं करेगा।

ऊर्जित करने की तारीख : 24.12.2026

क्रम सं.	खंड	किमी./चैनेज से	किमी./चैनेज तक
1.	उत्तर मध्य रेलवे के झाँसी मंडल के मध्य प्रदेश के मुरैना और श्योपुर जिले के सबलगढ़ (रहित)-बीरपुर (सहित) खंड	Mast Location 118/08	Mast Location 188/17

2653/26 (PH)

उप मुख्य बिजली इंजीनियर/निर्माण
उत्तर मध्य रेलवे, आगरा

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051
पंजीकृत कार्यालय: कॉमसेंन आईटी पार्क, टॉवर बी, पहली मंजिल, नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई - 600116, टीएन

अचल संपत्ति के लिए कब्जे का नोटिस [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

चूँकि अधोहस्ताक्षरी, एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी [राष्ट्रीय आवास बैंक (भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली) के साथ विधिवत पंजीकृत] (जिसे आगे "एसएमएफएफसी" कहा जाएगा) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत नीचे उल्लिखित दिनांकित मांग सूचना जारी करते हैं, जिसमें आपसे, उधारकर्ताओं के रूप में, (नीचे उल्लिखित नाम) उक्त सूचना में उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज की राशि, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया है। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को, एतद्द्वारा उक्त संपत्ति से लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन "SMHFC" के प्रभार के अधीन होगा यहाँ उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए।

स. क्रं.	उधारकर्ता (एस)/ गारंटर (एस) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण (अचल संपत्ति)	डिमांड नोटिस दिनांक और राशि	कब्जा की तिथि
1	लैन :- 604338311828002 एवं 604338011686160 1.अनूप सिंह 2. रूवी गुर्जर	यह पूरी संपत्ति प्लॉट नंबर 03/04 भाग, वार्ड नंबर 30, भूमि सर्वे नंबर 503, मौजा सिकारपुर, तहसील और जिला मुरैना 476001 (म.प्र.) में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 1080 वर्ग फुट है। इस संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में सड़क (20 फीट), पश्चिम में किसी अन्य का घर, उत्तर में प्लॉट नंबर 04 का हिस्सा, और दक्षिण में प्लॉट नंबर 01 और 02।	17.08.2026 रू. 16,10,569.23/- (सोलह लाख दस हजार पांच सौ उनहत्तर और तेईस पैसे मात्र) 10.08.2026 तक	20.11.2026
	लैन :- 604339511201996 1. ओंकार सिंह 2.शारदा देवी 3. करस देव डेयरी	सर्वे नंबर 387, ग्राम पमाया, वार्ड नंबर 1 पमायागांव, तहसील बमोर, जिला मुरैना (म.प्र.) में स्थित 800 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली संपत्ति। इस संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में फूल सिंह का घर, पश्चिम में रामनिवास व अन्य का घर, उत्तर में 10 फीट चौड़ी सड़क, और दक्षिण में 15 फीट चौड़ी सड़क।	17.08.2026 रू. 6,07,484.67/- (छह लाख सात हजार चार सौ चौरासी और सड़सठ पैसे मात्र) 10.08.2026 तक	20.11.2026
	लैन :- 604339211799501 एवं 604339411803463 1. रवि सिंह गुर्जर 2. प्रियंका	प्लॉट नंबर 07 और प्लॉट नंबर 08 के एक हिस्से (सर्वे नंबर 243 का भाग) पर स्थित पूरी संपत्ति, जो श्रीधा विहार, फेज-2, ग्राम महरापुरा गिर्द, तहसील और जिला ग्वालियर (म.प्र.) में है, का कुल क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट है। इस संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व में प्लॉट नंबर 22 और 21 (मकान सहित), पश्चिम में सड़क, उत्तर में प्लॉट नंबर 08 (मकान सहित), और दक्षिण में अन्य मकान।	17.08.2026 रू. 42,26,657.47/- (बयालीस लाख छब्बीस हजार छह सौ सत्तावन और सैंतालीस पैसे मात्र) 10.08.2026 तक	20.11.2026

स्थान: मुरैना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
दिनांक: 20.11.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड।